अंक - 55
जनवरी - जून 2015

ISSN. 0972-5881

ग्रामीण विकास समीक्षा

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030. (भारत)

अनुक्रम

क्र.सं.	विषय एवं लेखक	पृ. सं.
1.	भारत में सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण-नागरिक समाज का योगदान ● डॉ. मंजू देवी शर्मा	1
2.	''भारत में पर्यावरण के संवर्धन एवं प्रदूषण की रोकथाम के लिए अपनाए जा रहे प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन'' ● जयश्री एस. मेहता *	47
3.	सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में नागरिक समाज की प्रासंगिकता ● डॉ. सुमित्रा देवी शर्मा	65
4.	सभ्य समाज को निगल रहा अंधविश्वासः समस्या एवं समाधान ● डॉ. सुमित्रा देवी शर्मा	87
5.	बेरोजगार युवकों के लिए बकरी पालन एक उत्तम व्यवसाय बृजमोहन, अनुपम कृष्णदीक्षित, खुश्याल सिंह एवं विजयकुमार	105
6.	निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में किये गये प्रयास ● डॉ. अनिल कुमार सिंह* उमा श्रीवास्तव	109
7.	21 वीं सदी के भारतीय समाज में दलित अस्मिता मुकेश कुमार	119
8.	राजस्थान में पंचायती राज के सुदृढीकरण की दिशा में अभिनव प्रयास ● डॉ. पूरण मल बैरवा	129
9.	दलितों का सामाजिक -आर्थिक विकास ● डॉ. आर. के. सक्सैना* राकेश कुमार	139
10.	ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका शोध सारांश ● डॉ. सुचित्रा शर्मा	155

10. ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

शोध सारांश

डॉ. सुचित्रा शर्मा*

देश की 68.70 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है। यही कारण है कि देश के संपूर्ण विकास में ग्रामीण विकास को नकारा नहीं जा सकता। भारत का विकास गांवों की गलियों से होकर गुजरता है, उस देश की आधी आबादी महिलाओं की है जिसमें उनकी भागीदारी को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

विकास में अपने इतने योगदान के बावजूद भी ग्रामीण महिलाएं आज हाशिये पर हैं तथा अपने जीवन की आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पितृसत्तात्मक सामाजिक जीवन-मूल्य हमारे संस्कारों में इस तरह गहरी पैठ बनाये हुये हैं कि जाने-अनजाने हमारे ही क्रियाकलाप उन्हें और मजबूत करते जाते हैं। महिलाएँ चाहे ग्रामीण हों या शहरी उनके विकास हेतु शासन द्वारा कई कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये, पर वे उतने प्रभावपूर्ण और सक्षम नहीं रहे और उनकी स्थिति को संपोषित नहीं कर पाये क्योंकि ये सभी कार्यक्रम व्यावहारिक तौर पर कहीं न कहीं महिला विकास की जमीनी हकीकत से दूर थे। बरसों से जमी, लिंग भेद पर आधारित हमारी सामाजिक व्यवस्था महिलाओं को सशक्त करने में अवरोधक का काम करती रही।

शासन द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और उनमें महिलाओं की सहभागिता के लिए उनमें जागरूकता और आत्मनिर्भर होने की इच्छा का होना जरूरी है, जिसे जनसहयोग और स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता से पूरा किया जा सकता है। ये संस्थाएँ महिलाओं को स्वयं ही पहचान कराने, जागृति लाने और नई आशा पैदा करने में उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है। साथ ही साथ ये संस्थाएँ प्रत्यक्ष कार्य करने, बाहरी तत्वों पर कम विश्वास रखने तथा स्वयं की आन्तरिक क्षमताओं को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक साधनों के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकता निर्धारित करने में सहायक की भूमिका निभा सकती हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से यही जानने का प्रयास किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास में सरकार के साथ गैर सरकारी संगठन क्या भूमिका निभाते

* शासकीय प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर, भिलई